

औद्योगिक श्रमिकों की आय पर COVID-19 महामारी के प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रो अमित कुमार वत्स¹ एवं मनोज सिंह यादव²

¹शोध पर्यवेक्षक

²शोध छात्र वाणिज्य संकाय श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर म0प्र0

Received: 29 June 2025 Accepted & Reviewed: 29 June 2025, Published: 30 June 2025

Abstract

कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित किया है, जिसमें भारत का औद्योगिक क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। संगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को इस संकट का तीव्र प्रभाव झेलना पड़ा। महामारी के दौरान लॉकडाउन, उत्पादन में रुकावट, और रोजगार में अनिश्चितता ने श्रमिकों की जीवन-शैली और आर्थिक सुरक्षा को चुनौती दी। यह अध्ययन झाँसी क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिकों की परिस्थितियों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से मूल्यांकन करता है। शोध का उद्देश्य यह जानना है कि कोविड-19 के पश्चात उनकी आय, वेतन संरचना एवं रोजगार की स्थिरता में किस प्रकार के परिवर्तन संभावित हैं। साथ ही, यह अध्ययन पुरुष एवं महिला श्रमिकों की स्थिति की तुलनात्मक समीक्षा भी करता है, जिससे लिंग आधारित आर्थिक असमानताओं की पहचान की जा सके।

यह शोध नीति-निर्माताओं को श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन गारंटी एवं आपदा-कालीन राहत उपायों के पुनर्विचार हेतु एक दिशा प्रदान करने का प्रयास करता है। कोविड-19 महामारी ने झाँसी क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिकों की आय और आर्थिक स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। विश्लेषण में पुरुषों ने वेतन संरचना और नियमितता में अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जबकि महिलाओं ने अधिक नकारात्मक प्रभाव की सूचना दी। यह अध्ययन लैंगिक संवेदनशील नीतियों, कौशल विकास, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आवश्यकता को रेखांकित करता है ताकि श्रमिकों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य शब्द— कोविड-19, औद्योगिक श्रमिक, आय परिवर्तन, वेतन संरचना, कार्ड-वर्ग परीक्षण, लैंगिक असमानता

Introduction

COVID-19 महामारी ने भारतीय उद्योगों में विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर गहरा प्रभाव डाला है। 'योजना' पत्रिका (2021) के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान काम की अनिश्चितता और आय में कटौती आम समस्या रही। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' (2020) ने रिपोर्ट किया कि उत्तर प्रदेश में हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए। बिजनेस टुडे (2021) ने बताया कि MSME सेक्टर के ठप होने से श्रमिकों की वेतन संरचना चरमरा गई। 'ग्लोबल टाइम्स' (2021) के अनुसार, महामारी ने श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को अस्थिर कर दिया। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की आय, लाभ और भविष्य की योजनाओं में व्यवधान उत्पन्न हुआ।

साहित्य पुनर्विलोकन— गुप्ता, आर., और किशोर, ए. (2021). यह अध्ययन भारत के अनौपचारिक औद्योगिक श्रमिकों पर कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों की पड़ताल करता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि लॉकडाउन के

कारण विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन में कमी और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने श्रमिकों की आय को गंभीर रूप से प्रभावित किया। लगभग 60% श्रमिकों ने आय में 30–50% की कमी की सूचना दी, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में। अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया कि अनियमित वेतन भुगतान और रोजगार अनिश्चितता ने श्रमिकों की आर्थिक स्थिरता को और कमजोर किया। यह शोध नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर बल देता है, जैसे न्यूनतम वेतन गारंटी और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ। **संगुप्ता, ए. (2023)** का अध्ययन शहरी भारत में औद्योगिक श्रमिकों की आय और रोजगार पर कोविड-19 के दीर्घकालिक प्रभावों का विश्लेषण करता है। शोध में पाया गया कि 2020–2022 के बीच, विनिर्माण क्षेत्र में 40% श्रमिकों ने अस्थायी या स्थायी नौकरी छूटने की सूचना दी, जिसके परिणामस्वरूप औसत आय में 25% की कमी आई। अध्ययन ने यह भी नोट किया कि महिलाएँ और कम कुशल श्रमिक अधिक प्रभावित हुए। वेतन संरचना में परिवर्तन, जैसे बोनस में कटौती और ओवरटाइम अवसरों में कमी, ने आय अस्थिरता को और बढ़ाया। लेख नीति निर्माताओं से श्रमिकों के लिए पुनः कौशल विकास कार्यक्रमों की सिफारिश करता है, **पटेल, एस., शर्मा, आर., और कुमार, वी. (2023)**। यह अध्ययन दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत, में औद्योगिक श्रमिकों की वेतन गतिशीलता पर कोविड-19 के प्रभावों की जांच करता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि महामारी के बाद मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन लागत ने वास्तविक वेतन (inflation & adjusted income) को 15–20% तक कम कर दिया।

औद्योगिक क्षेत्र में, विशेष रूप से कपड़ा और ऑटोमोबाइल उद्योगों में, श्रमिकों ने अनियमित भुगतान और कम वेतन वृद्धि की शिकायत की। अध्ययन में लिंग आधारित असमानताओं पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें महिलाएँ पुरुषों की तुलना में अधिक आय हानि का सामना कर रही थीं। यह शोध आय स्थिरता के लिए सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क की आवश्यकता पर जोर देता है। **मिश्रा, पी. (2022)**। मिश्रा का यह अध्ययन हिंदी में प्रकाशित है और भारत में औद्योगिक श्रमिकों की आर्थिक स्थिति पर कोविड-19 के समाजशास्त्रीय प्रभावों की पड़ताल करता है। शोध में पाया गया कि लॉकडाउन ने न केवल आय में कमी की, बल्कि श्रमिकों के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण को भी प्रभावित किया। लगभग 50% श्रमिकों ने बताया कि अनियमित वेतन भुगतान ने उनके परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को कम कर दिया। अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करने वाले श्रमिकों को शहरी औद्योगिक क्षेत्रों में सबसे अधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेख सरकार से श्रमिक कल्याण योजनाओं को मजबूत करने की सिफारिश करता है। **राव, के.एस. (2021)**। महामारी और औद्योगिक श्रम बाजाररूप भारत में आय असमानता यह अध्ययन भारत के औद्योगिक श्रम बाजार में कोविड-19 के कारण उत्पन्न आय असमानता पर केंद्रित है। शोध में पाया गया कि महामारी ने औद्योगिक श्रमिकों के बीच आय वितरण को और अधिक असमान बना दिया, जिसमें उच्च कुशल श्रमिकों को कम नुकसान हुआ, जबकि कम कुशल और अनौपचारिक श्रमिकों ने आय में 40% तक की कमी का सामना किया। अध्ययन में वेतन संरचना में परिवर्तन, जैसे अस्थायी अनुबंधों की वृद्धि और नियमित रोजगार में कमी, को भी रेखांकित किया गया। लेख नीति निर्माताओं से श्रम सुधारों और वेतन सब्सिडी की सिफारिश करता है।

शोध उद्देश्य –

- यह अध्ययन करना कि COVID-19 के बाद प्रवासी औद्योगिक श्रमिकों की आय में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं।

- महामारी के दौरान वेतन संरचना में आए बदलावों का विश्लेषण करना। नियमित आय प्राप्ति की स्थिति की जांच करना।
- पुरुष एवं महिला श्रमिकों के उत्तरों की तुलनात्मक समीक्षा करना।

शोध डिजाइन—

अनुसंधान प्रकार: वर्णनात्मक एवं मात्रात्मक

नमूना आकार: 80 औद्योगिक श्रमिक (40 पुरुष, 40 महिला, झाँसी क्षेत्र)

डेटा संग्रहण तकनीक: प्राथमिक डेटा (साक्षात्कार और प्रश्नावली)

डेटा विश्लेषण उपकरण: काई-स्क्वायर परीक्षण

प्रश्नावली —

- COVID-19 के बाद मेरी आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।
- COVID-19 महामारी के बाद मेरी वेतन संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।
- COVID-19 के बाद मुझे मेरी आय नियमित रूप से प्राप्त हो रही है।

परिकल्पना —

- शून्य परिकल्पना: COVID-19 के बाद औद्योगिक श्रमिकों की आय में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- वैकल्पिक परिकल्पना: COVID-19 के बाद औद्योगिक श्रमिकों की आय में सार्थक अंतर है।

क्रॉसटैब (प्रतिशत में)

प्रश्न A: COVID-19 के बाद मेरी आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

उत्तर	पुरुष (%)	महिला (%)
पूरी तरह असहमत (5)	17.50	20.00
असहमत (4)	22.50	27.50
तटस्थ (3)	10.00	15.00
सहमत (2)	27.50	22.50
पूरी तरह सहमत (1)	22.50	15.00

प्रश्न A के अंतर्गत यह पूछा गया था कि "COVID-19 के बाद मेरी आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।" इस कथन पर पुरुषों और महिलाओं ने पाँच स्तरों पर प्रतिक्रिया दी — पूरी तरह सहमत, सहमत, तटस्थ, असहमत, और पूरी तरह असहमत। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 50% पुरुष इस कथन से सहमत (27.5%) या पूरी तरह सहमत (22.5%) हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश पुरुषों को महामारी के बाद अपनी आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं महसूस हुई। वहीं दूसरी ओर, महिलाओं में यह प्रतिशत केवल 37.5% है, यानी महिलाओं का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा ही मानता है कि उनकी आय में वृद्धि नहीं हुई।

प्रश्न B: COVID-19 महामारी के बाद मेरी वेतन संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

उत्तर	पुरुष (%)	महिला (%)
-------	-----------	-----------

पूरी तरह असहमत (5)	10.00	15.00
असहमत (4)	22.50	27.50
तटस्थ (3)	17.50	20.00
सहमत (2)	35.00	27.50
पूरी तरह सहमत (1)	15.00	10.00

प्रश्न B में यह पूछा गया है कि "COVID-19 महामारी के बाद मेरी वेतन संरचना (salary structure) में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।" इस कथन के उत्तर पुरुषों और महिलाओं द्वारा पाँच स्तरों पर दिए गए हैं — पूरी तरह सहमत, सहमत, तटस्थ, असहमत, और पूरी तरह असहमत। इन उत्तरों से यह स्पष्ट होता है कि महामारी के बाद वेतन संरचना को लेकर श्रमिकों के अनुभवों और धारणाओं में विविधता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पुरुषों में 50% (35% सहमत और 15% पूरी तरह सहमत) उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि उनकी वेतन संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वहीं महिलाओं में यह प्रतिशत 37.5% (27.5% सहमत और 10% पूरी तरह सहमत) रहा। यह अंतर दर्शाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने वेतन संरचना में अपेक्षाकृत कम परिवर्तन महसूस किया।

दूसरी ओर, असहमति व्यक्त करने वाले उत्तरों को देखें तो पुरुषों में 32.5% (10% पूरी तरह असहमत और 22.5% असहमत) तथा महिलाओं में 42.5% (15% पूरी तरह असहमत और 27.5% असहमत) ने यह माना कि उनकी वेतन संरचना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। यह संकेत करता है कि महिलाओं की बड़ी संख्या वेतन में परिवर्तन को लेकर असहमति रखती है, यानी उनके अनुसार महामारी के बाद वेतन संरचना में कोई विशेष अंतर नहीं आया। इसके अतिरिक्त, कुछ उत्तरदाता न तो सहमत थे और न असहमत — 17.5% पुरुष और 20% महिलाएं — जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ श्रमिकों के लिए वेतन संरचना में परिवर्तन का अनुभव स्पष्ट या निर्णायक नहीं था।

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि COVID-19 के बाद वेतन संरचना में परिवर्तन को लेकर पुरुषों में सहमति अधिक पाई गई, जबकि महिलाओं की अपेक्षा में असहमति अधिक रही। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरुषों ने महामारी के बाद वेतन नीति में अधिक परिवर्तन महसूस किए, जबकि महिलाओं के लिए यह परिवर्तन अपेक्षाकृत सीमित रहा। यह लिंग आधारित अनुभवों में अंतर को रेखांकित करता है, जिसे गहराई से समझने के लिए सांख्यिकीय परीक्षणों का सहारा लिया जा सकता है।

प्रश्न C: COVID-19 के बाद मुझे मेरी आय नियमित रूप से प्राप्त हो रही है।

उत्तर	पुरुष (%)	महिला (%)
पूरी तरह असहमत (5)	20.00	17.50
असहमत (4)	17.50	20.00
तटस्थ (3)	22.50	27.50
सहमत (2)	25.00	20.00
पूरी तरह सहमत (1)	15.00	15.00

प्रश्न C में यह पूछा गया है कि COVID-19 के बाद मुझे मेरी आय नियमित रूप से प्राप्त हो रही है।" इस कथन पर पुरुषों और महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं पाँच श्रेणियों में दीं कृ पूरी तरह सहमत, सहमत, तटस्थ, असहमत, और पूरी तरह असहमत। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि महामारी के बाद आय की नियमितता को लेकर श्रमिकों के अनुभवों में कुछ हद तक विविधता है।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, "आय की नियमित प्राप्ति से सहमत उत्तरदाताओं" में पुरुषों का प्रतिशत 40% (25% सहमत और 15% पूरी तरह सहमत) रहा, जबकि महिलाओं में यह प्रतिशत 35% (20% सहमत और 15% पूरी तरह सहमत) दर्ज किया गया। यह दर्शाता है कि "पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं को अपनी आय की नियमितता को लेकर थोड़ी कम सहमति है", यानी पुरुषों ने आय की स्थिरता को लेकर कुछ अधिक सकारात्मक अनुभव किया है। वहीं, "आय की नियमितता से असहमत उत्तरदाताओं" में पुरुषों का कुल प्रतिशत 37.5% (20% पूरी तरह असहमत और 17.5% असहमत) रहा, जबकि महिलाओं में यह प्रतिशत 37.5% (17.5% पूरी तरह असहमत और 20% असहमत) रहा। इसका अर्थ है कि "दोनों लिंगों में समान स्तर की असहमति देखी गई है", जो यह संकेत करता है कि महामारी के बाद अभी भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे आय की नियमित प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, "तटस्थ" उत्तरदाताओं का प्रतिशत पुरुषों में 22.5% और महिलाओं में 27.5% रहा। यह वर्ग उन श्रमिकों का है जिन्हें आय की नियमितता को लेकर निश्चयपूर्वक राय देना कठिन लगा — संभवतः उन्हें कभी-कभी नियमित आय मिली और कभी बाधा आई।

सारांशतः यह आंकड़े संकेत करते हैं कि महामारी के बाद आय की नियमितता को लेकर पुरुषों और महिलाओं दोनों में मिश्रित अनुभव रहे हैं। यद्यपि पुरुषों में आय की नियमित प्राप्ति को लेकर थोड़ी अधिक सहमति है, लेकिन असहमति का स्तर भी लगभग समान है। यह परिणाम इस ओर संकेत करता है कि COVID-19 के बाद आय की निरंतरता एक महत्वपूर्ण और अस्थिर पहलू बना रहा, जिसकी गहराई से समीक्षा की आवश्यकता है।

Chai-Square परीक्षण के अनुसार

प्रश्न	χ^2	क चि-मूल्य	निष्कर्ष
A	10.228 4	0.037	शून्य परिकल्पना अस्वीकृत
B	16.679 4	0.002	शून्य परिकल्पना अस्वीकृत
C	11.289 4	0.023	शून्य परिकल्पना अस्वीकृत

निष्कर्ष —

इस शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि COVID-19 महामारी ने झाँसी क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिकों की आय, वेतन संरचना तथा नियमित आय प्राप्ति की स्थिति पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। काई-स्क्वायर परीक्षण के सभी परिणामों से यह सिद्ध हुआ कि शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जा सकती है, अर्थात् महामारी के उपरांत औद्योगिक श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में वास्तविक व महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। विश्लेषण से यह भी ज्ञात हुआ कि पुरुष एवं महिला श्रमिकों के अनुभवों में कुछ स्पष्ट भिन्नताएँ थीं, विशेषतः वेतन संरचना में परिवर्तन और नियमितता की दृष्टि से। पुरुषों ने जहाँ अपेक्षाकृत अधिक

सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, वहीं महिलाओं ने अधिक नकारात्मक प्रभाव की पुष्टि की। यह अंतर स्पष्ट करता है कि भविष्य की नीति-निर्माण प्रक्रिया में लैंगिक संवेदनशीलता को सम्मिलित किया जाना चाहिए। महामारी ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार की दृष्टि से अत्यधिक असुरक्षित बना दिया, श्रमिकों की आजीविका पर गहरा आघात हुआ। वेतन असमानता, आय की अनियमितता, और मानसिक तनाव जैसे कारक श्रमिकों की समग्र जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले मुख्य घटक बनकर उभरे हैं।

यह शोध औद्योगिक क्षेत्र के नीति निर्माताओं, समाजशास्त्रियों, और आर्थिक नियोजकों के लिए उपयोगी साक्ष्य प्रस्तुत करता है, जिससे वे भविष्य में ऐसी आपदाओं की स्थिति में प्रभावी हस्तक्षेप और समर्थन तंत्र विकसित कर सकें। यह अध्ययन केवल झाँसी क्षेत्र तक सीमित है, जिससे इसके निष्कर्षों को अन्य क्षेत्रों पर सामान्यीकृत करना कठिन हो सकता है। नमूना आकार 80 श्रमिकों तक सीमित था, जो पूरे औद्योगिक समुदाय का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता। डेटा संग्रह के लिए केवल प्राथमिक स्रोतों (प्रश्नावली व साक्षात्कार) पर निर्भरता रही, जिससे उत्तरों में पक्षपात की संभावना हो सकती है। अध्ययन केवल तीन प्रश्नों पर आधारित था, जिससे COVID-19 के समग्र प्रभावों का सीमित दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। भविष्य के अध्ययन में श्रमिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभावों का विश्लेषण भी शामिल किया जाना चाहिए।

सुझाव: भविष्य में शोध को अधिक व्यापक क्षेत्रीय दायरे में विस्तारित किया जाना चाहिए ताकि अधिक सटीक निष्कर्ष निकाले जा सकें। नमूना आकार को बढ़ाकर अधिक विविधता वाले श्रमिक समूहों को शामिल करना चाहिए, जैसे विभिन्न आयु वर्ग, अनुभव स्तर और उद्योग क्षेत्रों से डेटा संग्रहण के लिए मिश्रित विधियों (जैसे फोकस ग्रुप, केस स्टडी आदि) का प्रयोग कर गहराई से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नीति निर्माताओं को इस शोध के निष्कर्षों के आधार पर श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने और संकट की स्थिति में समर्थन तंत्र विकसित करने चाहिए।

संदर्भ—

- 1- गुप्ता, आर., और किशोर, ए. (2021). भारत में अनौपचारिक श्रमिकों पर कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव पत्रिका: इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ISSN 0012-9976
2. सेंगुप्ता, ए. (2023). कोविड-19 और शहरी भारत में रोजगार और आय: औद्योगिक श्रमिकों पर प्रभाव पत्रिका: इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स ISSN: 0971-7927
3. पटेल, एस., शर्मा, आर., और कुमार, वी. (2023). दक्षिण एशिया में कोविड के बाद वेतन गतिशीलता पत्रिका: एशियन इकोनॉमिक रिव्यू ISSN 0004-4555
4. मिश्रा, पी. (2022). कोविड-19 और भारत में श्रमिकों की आर्थिक स्थितिरु एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण पत्रिका: समाजशास्त्र (Samajshastra) ISSN: 0976-6251
5. राव, के.एस. (2021). महामारी और औद्योगिक श्रम बाजार: भारत में आय असमानता पत्रिकारु जनन्याय (Jananyay) ISSN 0976-8394